जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 110 प्रभात चूरू, गुरुवार 18 अगस्त, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

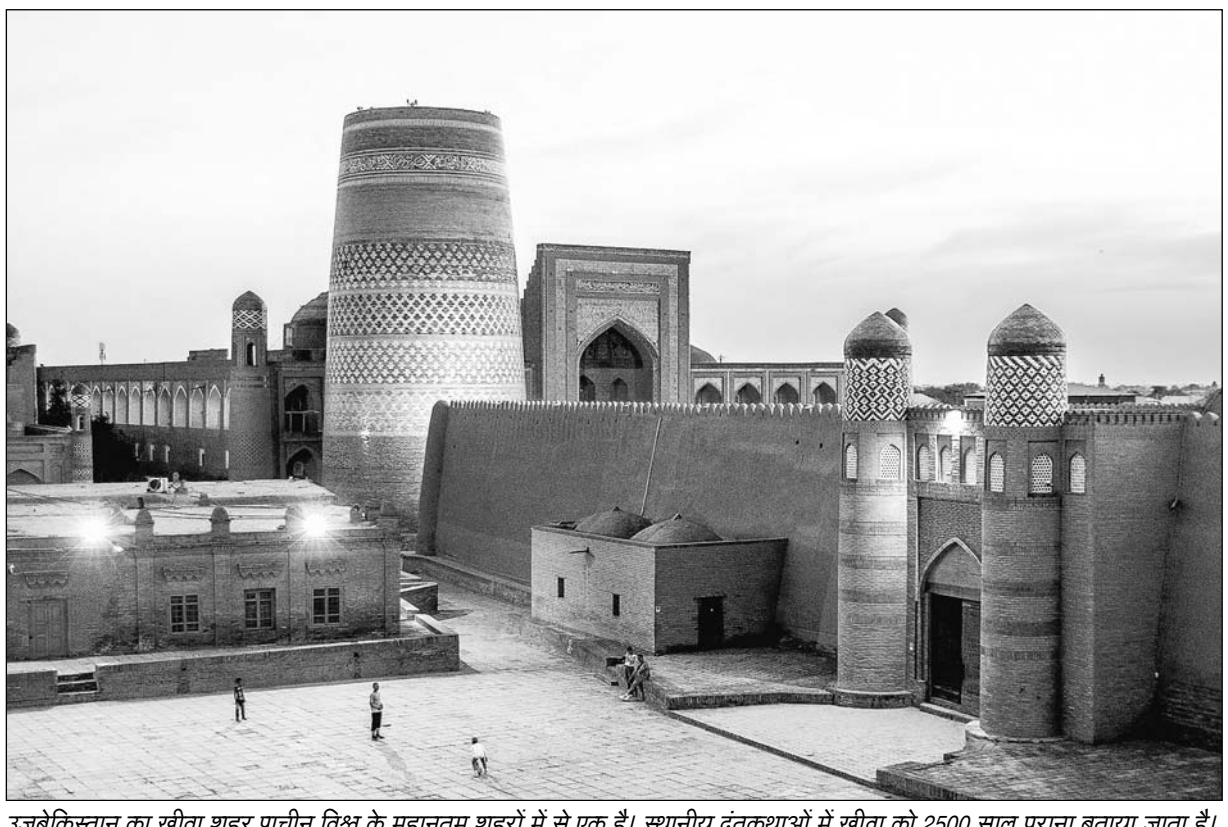

उज़बेकिस्तान का खीवा शहर प्राचीन विश्व के महानतम शहरों में से एक है। स्थानीय दंतकथाओं में खीवा को 2500 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि बाइबल के किरदार ''नोआ'' के एक पुत्र, शैम ने एक कुआं खोदा, जिसका पानी मीठा था। पानी पीने वाले कहते थे ''खे वाख,'' अर्थात् ''क्या आनंद है।'' पुरातात्विक सबूत इसे छठी सदी का बताते हैं। ईसापूर्व दसवीं सदी के हॉरी क्रॉनिकल्स में भी खीवा का उल्लेख है। अरब विद्वान अल इस्ताखरी ने भी खीवा को उस दौर के 30 सबसे बड़े शहरों में से एक बताया था और यह भी कहा था कि खीवा किले की स्थापना नोआ के पुत्र ने रेत पर की थी। खोरेज़्म क्षेत्र में खीवा सबसे लोकप्रिय शहर है। खोरेज़्म में अमू दरिया नाम की नदी बहती है, जो इस क्षेत्र का मुख्य जीवन स्रोत है। यह इस्लाम का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसमें 90 से अधिक मस्जिदें व 60 मदरसे हैं। शहर की एतिहासिक इमारतें इस देश में मिलने वाली अन्य एतिहासिक इमारतों से बहुत अलग हैं। ऊंची कलात्मक मीनारें, भव्य मदरसे और मस्जिदें, बाजार, मध्य कालीन महल और मकबरे, प्राचीन परम्पराएं और सबसे बढ़कर यहाँ की मेहमान नवाज़ी, लोगों को लुभाती है। कैराकुम और केज़ोलकम रेगिस्तानों के बीच में होने के कारण खीवा शहर ग्रेट सिल्क रोड से ईरान व बुखारा जाने वाले काफिलों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पोस्ट व रुकने का स्थान बन गया। एलैक्ज़ैण्डर द ग्रेट, अरब के लोगों, चंगेज़ खान और अमीर तिमूर ने बार-बार इस शहर को तहस-नहस किया। एक समय खीवा सैन्ट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट था। खीवा शहर का इतिहास बेहद रोचक और बहुआयामी है। यह शहर, जिसे आउटडोर म्यूज़ियम भी कहा जाता है, दो भागों में विभक्त है। बाहरी शहर, डिचान काला, जहाँ अधिकतर खीवा निवासी रहते हैं, तथा ऐतिहासिक भीतरी शहर इचन काला, जो किसी लाइफसाइज़ रेत के किले जैसा दिखता है। यहीं पर खीवा के अधिकतर आकर्षण मौजूद हैं। खीवा में कुतली मुराद इनाक मदरसा और 17 वीं सदी की इमारत, खान अनुष मोहम्मद का स्नानागार देखने लायक हैं। यहाँ की हरेक मस्जिद और मदरसा अपने आप में अनोखा है। यह शहर अपने बाजार के लिए भी विख्यात है, जहां सुंदर कालीन, कशीदाकारी की वस्तुएं, सैरेमिक्स आदि कलाकृतियां खरीदी जा सकती हैं। यह उज़बेकिस्तान का पहला शहर है जिसे युनैस्को ने, 1991 में, युनैस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट का दर्जा दिया।

मोदी-शाह ने भाजपा पर अपनी पूरी पकड़ दर्शायी

नितिन गडकरी व शिवराज सिंह चौहान, दोनों की संसदीय बोर्ड व केन्द्रीय चुनाव कमेटी की सदस्यता रिन्यु नहीं करवायी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। पार्टी पर अपनी लगातार पकड़ का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आज सुनिश्चित कर दिया कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के निर्णय लेने वाली शीर्ष कमेटियों- संसदीय बोर्ड तथा केन्द्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया जाए।

पार्टी के निर्णय लेने वाले इन दोनों शीर्ष मंचों का पुनर्गठन करते हुये, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इन दोनों में से किसी फोरम में शामिल नहीं किया है, वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा तथा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल इनमें शामिल कर लिये गये हैं।

योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने भाजपा को दूसरे अप्रत्याशित रूप से दूसरे कार्यकाल के लिये राज्य की सत्ता में पहुँचाया था, को इन दोनों फोरमों से बाहर रखा जाना चौंकाने वाला है क्योंकि ऐसी चर्चाएँ थीं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की लगातार दूसरी बार जीत के लिये पुरस्कृत करते हुये, योगी को निर्णय लेने वाले सर्वोच्च फोरमों में शामिल किया जायेगा।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाये रखना चाहती है। योगी विभिन्न कार्यक्रमों तथा महत्वपूर्ण घटनाओं और आयोजनों के जरिये, स्वयं को प्रधानमंत्री पद के लिये उपयुक्त एवं सामर्थ्यवान नेता के रूप में प्रोजैक्ट करते आ रहे हैं।

पार्टी का पुर्नगठित संसदीय बोर्ड, जिसमें छः नये चेहरे- बी.एस. येदियुरप्पा, सर्बानन्द सोनोवाल के. लक्ष्मण, इक़बाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव तथा सत्यनारायण जाटिया- शामिल किये गये हैं, नरेन्द्र मोदी-अमित शाह के दौर की भाजपा के सर्वोच्च सोपानों में पीढ़ीगत तथा राजनैतिक बदलाव का संकेत देता है।

संसदीय बोर्ड भाजपा का सर्वोच्च फोरम है, जो मुख्यमंत्रियों, प्रांतीय अध्यक्षों तथा अन्य अति महत्वपूर्ण भूमिकाओं या पदों के बारे में निर्णय लेता है।

नितिन गडकरी, जो आर.एस.एस. के चहेते हैं, को इस सर्वोच्च कमेटी से हटाया जाना इस फेरबदल में सबसे ज्यादा स्तब्ध कर देने वाला निर्णय है। गडकरी, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं तथा पार्टी परम्परागत रूप से अपने पूर्व अध्यक्षों को पार्टी के निर्णय लेने वाली इस सर्वोच्च कमेटी में रखती रही है। पार्टी के सैद्धांतिक परामर्शदाता आर.एस.एस. के साथ गहरे जुड़ाव के कारण गडकरी अब तक, उनके द्वारा अपनी ही सरकार पर प्रायः किये जाने वाले कटाक्षों के बावजूद, इन कमेटियों में बने हुये थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इन दिनों मोदी-शाह की इच्छानुरूप बने हुये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **साथ ही यू.पी. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पार्टी की इन दोनों सर्वोच्च ''डिसिज़न मेकिंग'' समिति का सदस्य नहीं बनवाया। पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फड़नवीस, जो महाराष्ट्र की शिंदे-भाजपा गठबंधन की सरकार के रचयिता हैं, को पार्लियामैंटरी बोर्ड व केन्द्रीय चुनाव कमेटी का सदस्य बनवाया। इन दोनों सर्वोच्च डिसिज़न मेकिंग बॉडी के अन्य नये सदस्य हैं, असम के सर्बानन्द सोनोवाल, जिन्होंने असम के मु.मंत्री पद का अपना दावा छोड़कर, हेमन्त बिस्वा सरमा, जो कि हाईकमान की पसन्द थे, को असम का मु.मंत्री बनवाया।**
- **अन्य नये सदस्य हैं, येदियुरप्पा, के.एल. लक्ष्मण, इक़बाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव व सत्यनारायण जटिया।**

बिहार में कोई सशक्त नेता नहीं ढूंढ पाना खल रहा है भाजपा को

भाजपा लगभग 17 साल (केवल बीच में दो साल को छोड़कर) तक जे.डी.यू. के साथ बिहार में सरकार का हिस्सा रही है, पर नेता की कमी पूरी नहीं कर पाई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। बिहार के लिये पुनः तैयार की गई रणनीति के हिस्से के रूप में, भाजपा स्व. रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों परस्पर विरोधी गुटों का विलय कराने की, उन्हें एक करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, पार्टी उन छोटी जाति आधारित पार्टियों तथा ग्रुपों के सम्पर्क में आने, उन तक अपनी पहुंच बनाने की भी कोशिश करेगी, जो अत्यधिक पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि भाजपा विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ भी अपने संबंध सुधारने की पहल शुरू कर दी है।

मंगलवार शाम को पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग, बड़े संगठनात्मक बदलाव करने की जरूरत के विषय में भी चर्चा हुई, जिससे एक ऐसी अति सक्रिय नेतृत्व टीम अस्तित्व में आ सके, जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े। पूववर्ती सरकार के अपेक्षाकृत छोटे कद के पूर्व उपमुख्यमंत्रियों ताराकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी की जगह पर, ई.बी.सी. समुदाय के किसी अच्छे वक्ता, जोशीले तथा गतिशील नेता की खोज शुरू हो गई है। भाजपा के पास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **अब नीतीश के गठबंधन तोड़कर जाने के बाद, पार्टी लम्बी-लम्बी मंथन बैठकें आयोजित कर रही है।**
- **कई नये-नये फार्मूलों पर विचार हो रहा है, जैसे रामविलास पासवान की पार्टी के दोनों धड़ों को एक करा जाये।**
- **विकासशील इंसान पार्टी से पुनः समझौता किया जाये।**
- **पार्टी के दो पुराने उप मुख्यमंत्रियों की जगह युवा, आक्रामक शैली वाले नेता, ढूंढे जायें, जो विधानसभा व विधानपरिषद में पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता नियुक्त हों।**
- **पार्टी को राज्य के लिए एक प्रभारी महासचिव की भी तलाश है, क्योंकि भूपेन्द्र यादव के केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद यह पद खाली पड़ा है।**
- **पार्टी ने तीन सूत्री समिति भी तैयार की है।**

'चुनाव लड़ना नहीं शिक्षा पाना मूल अधिकार'

जयपुर, 17 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में आयु सीमा में छूट और अंतिम सेमेस्टर के छात्र को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देने से जुडे मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है ना की छात्रसंघ चुनाव लड़ने का।

इसके साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता छात्र नेताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिकाओं पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। एक्टिंग सीजे एमएम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए एक छात्र द्वारा दायर की गई याचिका पर मौखिक टिप्पणी की।**

'बलात्कारियों को रिहा करना राज्य सरकार का ही फैसला'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। कांग्रेस ने गुजरात सरकार के इस झूठ को बुधवार को उजागर किया कि उसने बिलकीस बानों गैंग रेप केस के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया हैं।

पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां एक प्रैस कांफ्रैंस में बताया कि जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्षमा करने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ ये निर्देश दिए थे कि केस का निस्तारण तीन माह के भीतर किया जाए।

उन्होंने राज्य सरकार के इस दावे की भी भर्त्सना की कि उन्हें माफी देने का आधार वर्ष 1992 की नीति थी तथा उन्हें वर्ष 2014 के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षमा नहीं किया गया हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पढ़ते हुए उन्होंने बताया कि ''गृह मंत्रालय के वर्ष 2014 के दिशा-निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन लोगों पर रेप, गैंग रेप तथा मर्डर जैसे घृणित अपराध सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सजा से माफी प्रदान नहीं की जा सकती।''

खेड़ा ने कहा कि जो नया तथ्य सामने आया है वह और भी अधिक चौंकाने वाला है। राज्य सरकार वर्ष 1992 की जिस कथित नीति का हवाला दे रही है, उसे गुजरात सरकार ने 8 मई 2013 को समाप्त कर दिया था और उस वक्त नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 8 मई के आदेश की एक कॉपी भी वितरीत की।

खेड़ा ने कहा कि एक अन्य तथ्य यह है कि राज्य सरकार को सैन्ट्रल एजेंसी द्वारा इन्वैस्टिगेट किए गए केस में दोषियों को माफी देने से पूर्व केन्द्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह का जवाब चाहा कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई अथवा नहीं। केन्द्र ने यदि सहमति प्रदान नहीं की तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह जेल एडवायज़री कमेटी के उन सदस्यों के नाम साझा करे जिन्होंने इन 11 दोषियों को माफी देने की सबसे पहले सिफारिश की थी और क्या मुख्यमंत्री की सरकार ने 8 मई 2013 के आदेश को शीर्ष अदालत के साथ साझा किया, जिसके जरिए वर्ष 1992 की नीति को रद्द कर दिया गया था। खेड़ा ने बिलकीस बानो के उन अपराधियों, जिन्होंने रेप किया, नापाक हरकत की, बच्चों की हत्या की और जिन्हें रेप और हत्या का दोषी पाया गया, के प्रति समाज की चुप्पी पर हैरानी जताई।

- **कांग्रेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कभी नहीं दिया कि, बिलकीस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाये।**

रोहिंग्यास को फ्लैट?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी इस योजना के लिए लताड़ा कि नई दिल्ली के बकरवाला में ई.डब्ल्यू.एस. (इकोनॉमिकलीवीकर सैक्शन्स) फ्लैट्स रोहिंग्याओं को दे दिए जाएं और उन्हें मदनपुर खादर से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

- **रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट देने की योजना के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की कड़ी निंदा की।**

एक प्रैस नोट में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस सम्बंध में कोई निर्देश नहीं दिया है क्योंकि रोहिंग्या अवैध शरणार्थी हैं और उन्हें भारत से जाना होगा। गृह मंत्रालय पहले ही उन्हें वापस भेजने के बारे में विदेश मंत्रालय के जरिए सम्बंधित देश से बात कर चुका है।

विज्ञप्ति कहती है कि रोहिंग्या जैसे अवैध विदेशियों को उनकी वापसी होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन (आई.ओ.ए.) के संचालन का कार्यभार संभालने और चार माह के भीतर नवीन चुनाव करवाने के लिए ओलम्पियन अभिनव बिन्द्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बायला देवी साईश्रम को नियुक्त किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन ओलम्पिक खिलाड़ियों, अभिनव बिन्द्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बी. देव साइश्रम को आई.ओ. सी. के संचालन और चार माह में चुनाव करवाने की जिम्मेवारी सौंपी है।**

कुछ ठीक नहीं है भाजपा की कर्नाटक इकाई में

कर्नाटक के प्रभारी महासचिव अरूण सिंह को कर्नाटक भेजा गया, पार्टी में व्याप्त ''कन्फ्यूज़न'' को सुलझाने के लिये

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अगस्त। भाजपा हाई कमान ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य के दिग्गज नेता बी.एस. येदियुरप्पा को बुधवार को पार्टी की शीर्ष निर्णय इकाई-भाजपा संसदीय बोर्ड और केन्द्रीय चयन कमेटी में पदोन्नत किया, लेकिन उसने इसी दिन पार्टी के कर्नाटक प्रभारी अरूण सिंह को राज्य के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पूर्व पार्टी को व्यवस्थित करने के लिए बैंगलोर भेजा।

नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बैंग्लोर में अतिव्यस्त राजनीतिक गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हांलाकि मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इससे इन्कार किया है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन की कथित रूप से रक्षा ना कर पाने को लेकर पिछले कुछ समय से हिंदू संगठनों के निशाने पर रहते आए हैं। उनके और भाजपा के लिए और भी अधिक परेशानी की बात यह है कि राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने विपक्ष को पार्टी पर प्रहार करने का साधन दे दिया हैं।

कर्नाटक के विधि मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने एक लीक्ड़ वीडियों में टिप्पणी की कि राज्य में सरकार नहीं चलायी जा रही है, बल्कि इसका अगले चुनावों तक प्रबन्धन भर किया जा रहा हैं। इस टिप्पणी ने पार्टी और मुख्यंमत्री को शर्मिंदा कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने जब इस टिप्पणी के लिए मंत्री को फटकार लगायी, तब मंत्री ने घोषणा की कि वह अपनी टिप्पणी के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं।

और इतना ही नहीं।

परिवहन मंत्री एवं भाजपा के दबंग नेता बी. श्रीरामुलू ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता एस. सिद्धारमैया फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी-1 एक व्यक्ति जो पिछले विधानसभा चुनवों में सिद्धारमैया से हार गया था, यदि अपने विरोधी की प्रशंसा करने लगे तो भृकुटियां तो तनती हैं। उन्होंने सिद्धारमैया को अपना अच्छा मित्र बताया।

इसके अलावा कुछ विधायक पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री के प्रति असंतोष व्यक्त करते आए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भाजपा से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद इन्हीं परिस्थितियों पर पार पाने के लिए भाजपा के राज्य प्रभारी अरूण को बैंगलोर भेजा गया है। पार्टी की राज्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **एक तरफ तो मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, हिन्दू संगठनों का लक्ष्य बने हुए हैं, और ये संगठन उन पर आरोप लगा रहे हैं कि, वे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों के जान लेवा हमलों से बचा नहीं पा रहे।**
- **दूसरी ओर उनकी सरकार के विधि मंत्री मधु स्वामी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें, विधि मंत्री ने साफ कहा कि, मुख्यमंत्री बोम्मई की सरकार नहीं चल रही। मु.मंत्री चुनाव तक केवल टाईम पास कर रहे हैं।**
- **इसी प्रकार, परिवहन मंत्री बी. श्रीरामुलू ने अजीबोगरीब टिप्पणी की कि, वे प्रसन्न होंगे अगर, कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मु.मंत्री सिद्धारमैया, पुनः मु.मंत्री बनें।**
- **शायद मु.मंत्री व पार्टी का मनोबल व हौंसला बढ़ाने के लिये ही, पूर्व मु.मंत्री येदियुरप्पा को पार्टी की ''सर्वोच्च डिसिज़न मेकिंग'' कमेटी, संसदीय बोर्ड व केन्द्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाकर, झाड़-पोंछ कर पुर्नस्थापित किया गया है। लिंगायत नेता येदियुरप्पा से उम्मीद की जा रही है कि, वे लिंगायत वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में संगठित कर लेंगे।**